

डिजिटल एवं नकदीकरण के लाभ एवं हानियों का एक अध्ययन

सारांश (Abstract)

डिजिटल तकनीक के विस्तार ने भारत में भुगतान की आदतों और वित्तीय व्यवहार को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है। मोबाइल आधारित भुगतान, UPI, कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने छोटे से छोटे लेन-देन को भी शीघ्र और सुविधाजनक बनाया है। दूसरी ओर, नकद अभी भी उन परिस्थितियों में उपयोगी है जहाँ इंटरनेट, बिजली, डिजिटल उपकरण या पर्याप्त डिजिटल दक्षता उपलब्ध नहीं होती। प्रस्तुत अध्ययन में डिजिटल तथा नकद भुगतान व्यवस्था के आर्थिक, सामाजिक और व्यवहारगत पक्षों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है तथा RBI, NPCI, IMF और World Bank की उपलब्ध सामग्री का उपयोग करता है। विश्लेषण से संकेत मिलता है कि डिजिटल भुगतान दक्षता, लेन-देन के रिकॉर्ड और दूरस्थ भुगतान में मजबूत है, जबकि नकद भुगतान तकनीकी निर्भरता से मुक्त और अनेक छोटे लेन-देन में सरल है। इसलिए भारतीय संदर्भ में दोनों माध्यमों को विरोधी विकल्प मानने के बजाय परिस्थितिनुसार पूरक माध्यमों के रूप में विकसित करना अधिक व्यावहारिक है।

मुख्य शब्द (Keywords)

डिजिटल भुगतान, नकद भुगतान, UPI, वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, भुगतान प्रणाली

1. प्रस्तावना

भुगतान प्रणाली किसी भी अर्थव्यवस्था की दैनिक गतिविधियों का आधार होती है। पिछले दशक में भारत में भुगतान का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की ओर स्थानांतरित हुआ है। स्मार्टफोन, बैंक खातों की व्यापक पहुंच और interoperable payment infrastructure ने इस परिवर्तन को गति दी। UPI ने विशेष रूप से व्यक्ति-से-व्यक्ति तथा व्यक्ति-से-व्यापारी भुगतान को सरल बनाया है।

27 फिर भी डिजिटल विस्तार को नकद के पूर्ण अंत के रूप में देखना उचित नहीं है। नकद की मांग व्यवहार,
28 सुविधा, अनिश्चितता तथा ऐसे क्षेत्रों से प्रभावित होती है जहाँ डिजिटल अवसंरचना सीमित है। इसीलिए
29 डिजिटल और नकद भुगतान के लाभ-हानियों का संतुलित अध्ययन आवश्यक है।

30 2. अध्ययन की आवश्यकता

31 डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के साथ उपभोक्ताओं के सामने सुविधा के साथ नए जोखिम भी आए
32 हैं। गलत लिंक पर क्लिक करना, फर्जी कॉल, social engineering, अनधिकृत लेन-देन और व्यक्तिगत
33 वित्तीय जानकारी की सुरक्षा जैसे प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं। दूसरी ओर, नकद भुगतान में चोरी, गुम होने
34 और लेन-देन के स्वचालित रिकॉर्ड के अभाव जैसी सीमाएँ हैं। इस पृष्ठभूमि में अध्ययन यह समझने का
35 प्रयास करता है कि विभिन्न परिस्थितियों में कौन-सा माध्यम अधिक उपयोगी हो सकता है।

36 3. अध्ययन के उद्देश्य

- 37 • डिजिटल भुगतान के स्वरूप और विकास को समझना।
- 38 • डिजिटल भुगतान से प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभों की पहचान करना।
- 39 • डिजिटल माध्यमों से जुड़े जोखिमों और व्यवहारगत चुनौतियों का विश्लेषण करना।
- 40 • नकद भुगतान की उपयोगिता और सीमाओं का अध्ययन करना।
- 41 • दोनों भुगतान माध्यमों की तुलनात्मक विशेषताओं को स्पष्ट करना।
- 42 • सुरक्षित, समावेशी और उपयोगकर्ता-केंद्रित भुगतान व्यवस्था के लिए सुझाव देना।

43 4. शोध प्रश्न

- 44 1. डिजिटल भुगतान किन कारणों से तेजी से स्वीकार किया जा रहा है?
- 45 2. डिजिटल भुगतान के साथ उपयोगकर्ताओं को किन प्रमुख जोखिमों का सामना करना पड़ता है?
- 46 3. नकद भुगतान किन परिस्थितियों में अभी भी अधिक व्यावहारिक है?
- 47 4. डिजिटल भुगतान वित्तीय समावेशन में किस प्रकार योगदान कर सकता है?
- 48 5. दोनों माध्यमों के बीच संतुलित व्यवस्था कैसे विकसित की जा सकती है?

49 5. शोध पद्धति (Research Methodology)

50 यह अध्ययन वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। शोध के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण के स्थान पर
51 द्वितीयक सामग्री का उपयोग किया गया है। RBI की वार्षिक रिपोर्टें, NPCI के UPI आंकड़ों तथा IMF और
52 World Bank की प्रकाशित सामग्री को आधार बनाया गया है। प्राप्त सूचनाओं को सुविधा, लागत, पहुंच,
53 सुरक्षा, पारदर्शिता और समावेशन जैसे आयामों पर व्यवस्थित करके तुलनात्मक रूप से समझाया गया है।
54 चूँकि अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, इसलिए इससे प्राप्त निष्कर्षों को सामान्य प्रवृत्तियों के रूप
55 में ग्रहण करना उचित है। किसी विशिष्ट जिले, आयु-वर्ग या सामाजिक समूह के लिए निष्कर्ष निकालने हेतु
56 अलग प्राथमिक सर्वेक्षण अपेक्षित होगा।

57 6. साहित्य समीक्षा

58 RBI की भुगतान प्रणाली संबंधी रिपोर्टें भारत में डिजिटल भुगतान की निरंतर वृद्धि तथा भुगतान
59 अवसंरचना के विस्तार को रेखांकित करती हैं। NPCI के आंकड़े UPI के बढ़ते लेन-देन को दर्शाते हैं।
60 IMF के विश्लेषणों में interoperable digital payment infrastructure को भारत के डिजिटल भुगतान
61 विस्तार का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। World Bank की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना संबंधी
62 सामग्री डिजिटल पहचान, भुगतान और डेटा-साझाकरण जैसी व्यवस्थाओं को व्यापक आर्थिक अवसरों से
63 जोड़ती है।

64 उपलब्ध साहित्य से यह भी स्पष्ट होता है कि तकनीकी पहुंच अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उपयोगकर्ता का
65 विश्वास, डिजिटल कौशल, शिकायत-निवारण तथा डेटा-सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएँ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के
66 स्थायी उपयोग के लिए आवश्यक हैं।

67 7. डिजिटल भुगतान : अर्थ एवं प्रमुख माध्यम

68 डिजिटल भुगतान वह प्रक्रिया है जिसमें धन का हस्तांतरण इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से किया जाता
69 है और भुगतान की पुष्टि डिजिटल माध्यम से होती है। भारत में UPI, IMPS, NEFT, कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग,
70 मोबाइल बैंकिंग और विभिन्न अधिकृत डिजिटल भुगतान साधन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन प्रणालियों
71 की विशेषता यह है कि उपयोगकर्ता भौतिक मुद्रा का आदान-प्रदान किए बिना भुगतान कर सकता है।

72 8. डिजिटल भुगतान के लाभ

- 73 • त्वरित लेन-देन और समय की बचत।
- 74 • दूरस्थ स्थान से भुगतान करने की सुविधा।
- 75 • लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होना।
- 76 • व्यापारियों के लिए भुगतान स्वीकार करने के अतिरिक्त विकल्प।
- 77 • नकदी रखने और जमा करने की कुछ परिचालन आवश्यकताओं में कमी।
- 78 • वित्तीय सेवाओं से जुड़ने और औपचारिक वित्तीय प्रणाली के उपयोग की संभावना में वृद्धि।
- 79 • बिल, शुल्क और नियमित भुगतान को स्वचालित या व्यवस्थित करना आसान होना।

80 9. डिजिटल भुगतान की सीमाएँ

- 81 • इंटरनेट, बिजली, डिवाइस या बैंकिंग प्रणाली पर निर्भरता।
- 82 • फिशिंग, social engineering और अन्य डिजिटल धोखाधड़ी का खतरा।
- 83 • गलत खाते या UPI ID पर भुगतान होने की संभावना।
- 84 • व्यक्तिगत एवं वित्तीय डेटा की सुरक्षा की आवश्यकता।
- 85 • कम डिजिटल साक्षरता वाले लोगों के लिए उपयोग में कठिनाई।
- 86 • तकनीकी खराबी या server/network समस्या के कारण अस्थायी बाधा।
- 87 • लगातार आसान भुगतान की सुविधा से कुछ उपयोगकर्ताओं में अनियोजित खर्च की संभावना।

88 10. नकदभुगतान के लाभ

- 89 • मोबाइल, इंटरनेट और बैंकिंग ऐप की आवश्यकता नहीं।
- 90 • नेटवर्क या बिजली बाधित होने पर भी सामान्यतः उपयोग संभव।
- 91 • छोटे स्थानीय लेन-देन में सरल और परिचित माध्यम।
- 92 • कम डिजिटल दक्षता वाले लोगों के लिए अपेक्षाकृत सहज।
- 93 • लेन-देन के समय डिजिटल credentials साझा करने की आवश्यकता नहीं।

94 11. नकदभुगतान की सीमाएँ

- 95 • धन चोरी या खोने की स्थिति में प्रतिपूर्ति कठिन हो सकती है।
- 96 • बड़ी राशि को सुरक्षित रखना और ले जाना असुविधाजनक।

- 97 • व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन के लिए स्वचालित डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता।
- 98 • व्यवसायों को नकदी गिनने, सुरक्षित रखने और बैंक में जमा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाने
- 99 पड़ सकते हैं।
- 100 • नकद आधारित कुछ लेन-देन में पारदर्शिता और औपचारिक रिकॉर्ड कम हो सकता है।

101 12. तुलनात्मक विश्लेषण

मापदंड	डिजिटल भुगतान	नकद भुगतान
गति	अधिकतर बहुत तेज	लेन-देन की स्थिति पर निर्भर
तकनीकी निर्भरता	अधिक	बहुत कम
रिकॉर्ड	डिजिटल रिकॉर्ड	स्वतः डिजिटल रिकॉर्ड नहीं
दूरस्थ भुगतान	बहुत सुविधाजनक	सीमित
साइबर जोखिम	प्रासंगिक	कम
भौतिक जोखिम	कम, पर डिजिटल जोखिम मौजूद	चोरी/गुम होने का जोखिम
डिजिटल साक्षरता	आवश्यक	बहुत कम आवश्यकता
छोटे स्थानीय भुगतान	सुविधाजनक	बहुत सरल

102 13. भारतीय संदर्भ में डिजिटल भुगतान

103 NPCI के UPI Product Statistics के अनुसार मई 2026 में UPI पर लगभग 23.20 अरब लेन-देन दर्ज

104 हुए और उनका कुल मूल्य लगभग ₹29.90 लाख करोड़ रहा। यह आंकड़ा डिजिटल भुगतान के विशाल

105 पैमाने को दर्शाता है। RBI की 2023-24 वार्षिक रिपोर्ट ने भी गैर-नकद खुदरा भुगतान में डिजिटल लेन-

106 देन की अत्यंत ऊँची हिस्सेदारी दर्ज की थी।

107 इन प्रवृत्तियों के बावजूद नकद की मांग बनी रहना इस बात का संकेत है कि भुगतान व्यवहार केवल

108 तकनीकी उपलब्धता से निर्धारित नहीं होता। सुविधा, विश्वास, आय, स्थानीय व्यापार की प्रकृति,

109 आपातकालीन जरूरत और डिजिटल अवसंरचना सभी इसकी भूमिका तय करते हैं।

110 14. वित्तीय समावेशन और डिजिटल विभाजन

111 डिजिटल भुगतान तब वित्तीय समावेशन का प्रभावी माध्यम बनता है जब उपयोगकर्ता के पास बैंक खाता,

112 उपयुक्त उपकरण, कनेक्टिविटी और आवश्यक कौशल उपलब्ध हों। ग्रामीण और कम-सुविधा वाले क्षेत्रों

113 में इन शर्तों में से किसी एक की कमी डिजिटल उपयोग को सीमित कर सकती है। इसलिए केवल ऐप या
114 QR उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है; प्रशिक्षण, स्थानीय भाषा, भरोसेमंद सहायता और शिकायत समाधान
115 भी जरूरी हैं।

116 15. साइबर सुरक्षा एवं उपभोक्ता जागरूकता

117 डिजिटल भुगतान में सुरक्षा तकनीक के साथ उपयोगकर्ता के व्यवहार पर भी निर्भर करती है। OTP, UPI
118 PIN, पासवर्ड और अन्य authentication जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए। अज्ञात
119 लिंक, संदिग्ध कॉल और अनधिकृत screen-sharing अनुरोधों से सावधानी आवश्यक है। भुगतान से
120 पहले प्राप्तकर्ता का नाम और राशि सत्यापित करना भी उपयोगी सुरक्षा अभ्यास है।

121 संस्थागत स्तर पर fraud monitoring, मजबूत authentication, समय पर alerts और प्रभावी
122 grievance redressal आवश्यक हैं। डिजिटल भुगतान पर विश्वास तभी टिकाऊ होगा जब उपयोगकर्ता
123 को समस्या होने पर सरल और शीघ्र सहायता उपलब्ध हो।

124 16. प्रमुख निष्कर्ष

- 125 • डिजिटल भुगतान भारत की भुगतान व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।
- 126 • UPI ने त्वरित और interoperable भुगतान को व्यापक स्तर पर संभव बनाया है।
- 127 • डिजिटल माध्यम रिकॉर्ड, सुविधा और दूरस्थ भुगतान में विशेष लाभ देते हैं।
- 128 • नकद भुगतान तकनीकी निर्भरता से मुक्त होने के कारण अभी भी प्रासंगिक है।
- 129 • डिजिटल सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता भुगतान व्यवस्था की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण घटक हैं।
- 130 • भविष्य की भुगतान व्यवस्था में डिजिटल और नकद दोनों विकल्पों का संतुलित सह-अस्तित्व अधिक
131 व्यावहारिक दिखाई देता है।

132 17. सुझाव

- 133 • स्थानीय भाषाओं में सुरक्षित डिजिटल भुगतान संबंधी जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाए जाएँ।
- 134 • कॉलेज, बैंक और सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से साइबर-सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए।
- 135 • कम-कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक और कम-तकनीकी भुगतान सुविधाओं को मजबूत
136 किया जाए।

- 137 • डिजिटल धोखाधड़ी की शिकायतों के समाधान को अधिक सरल और त्वरित बनाया जाए।
- 138 • वरिष्ठ नागरिकों तथा कम डिजिटल दक्षता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सरल interfaces विकसित
- 139 किए जाएँ।
- 140 • भुगतान सेवाओं में डेटा-सुरक्षा और उपयोगकर्ता की सहमति को प्राथमिकता दी जाए।
- 141 • नकद को समाप्त करने के बजाय सुरक्षित, वैध और आवश्यक परिस्थितियों में उपलब्ध विकल्प के
- 142 रूप में बनाए रखा जाए।

143 18. निष्कर्ष

144 अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि डिजिटल भुगतान आधुनिक आर्थिक गतिविधियों में दक्षता और
145 सुविधा बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण साधन है, परंतु इसकी उपयोगिता सुरक्षित तकनीक और सक्षम उपयोगकर्ता
146 पर निर्भर करती है। नकद भुगतान की सीमाएँ होने के बावजूद वह तकनीकी अवसंरचना से स्वतंत्रता तथा
147 सरलता के कारण अनेक परिस्थितियों में उपयोगी बना हुआ है।

148 अतः भारतीय संदर्भ में भुगतान व्यवस्था को केवल नकदी से डिजिटल की ओर एकतरफा संक्रमण के रूप
149 में देखना पर्याप्त नहीं होगा। अधिक उपयुक्त दृष्टिकोण ऐसी समावेशी व्यवस्था का निर्माण है जिसमें
150 डिजिटल भुगतान को सुरक्षित एवं सुलभ बनाया जाए और आवश्यक परिस्थितियों में नकद विकल्प भी
151 उपलब्ध रहे।

152 19. अध्ययन की सीमाएँ

153 प्रस्तुत शोध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है और इसमें प्रत्यक्ष प्रश्नावली या क्षेत्रीय सर्वेक्षण शामिल नहीं है।
154 इसलिए उपयोगकर्ता-विशिष्ट अनुभवों, व्यवहार और स्थानीय अंतर को मापने के लिए आगे प्राथमिक शोध
155 की आवश्यकता होगी। भविष्य के अध्ययन में ग्रामीण-शहरी, आयु, शिक्षा, व्यवसाय और डिजिटल दक्षता
156 के आधार पर नमूना सर्वेक्षण किया जा सकता है।

157 20. संदर्भ सूची (References)

- 158 6. Reserve Bank of India. (2024). Annual Report 2023-24. Department of Payment and
159 Settlement Systems.

- 160 7. National Payments Corporation of India. (2026). Unified Payments Interface (UPI)
161 Product Statistics.
- 162 8. International Monetary Fund. (2021). India's Approach to Open Banking: Some
163 Implications for Financial Inclusion. IMF Working Paper 2021/052.
- 164 9. International Monetary Fund. (2025). India's Frictionless Payments. Finance &
165 Development.
- 166 10. World Bank. (2026). Global Digital Public Infrastructure Program: From Foundations
167 to Scale.
- 168 11. World Bank. Inclusive Digital Financial Services: A Reference Guide for Policymakers
169 and Regulators.

170 **शोध -पत्र में प्रयुक्त प्रमुख आधिकारिक स्रोत**

- 171 National Payments Corporation of India (NPCI): UPI Product Statistics
- 172 Reserve Bank of India (RBI): Annual Reports and Payment System publications
- 173 International Monetary Fund (IMF): Digital payments and financial inclusion research
- 174 World Bank: Digital Public Infrastructure and Digital Financial Services